(c) The post was in the grade of Rs. 250-380 in 1964 and now it is in the grade of Rs. 205-280.

(d) The post was downgraded on the basis of the worth of the charge and the higher grade was allotted to another unit in the Division.

Industrial survey of Bahraich District (U.P.)

2234. SHRI B. R. SHUKLA : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether a survey of industrial potentialities was made some time back in the District of Bahraich (U.P.) and if so, what industries were suggested to be set up; and

(b) whether any action has been taken by Government to set up any public undertakings or to aid any private enterprise to industrialise the district ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI SIDDHESHWAR PRASAD) : (a) and (b). Bahraich is one among the 35 backward districts of U.P. which are eligible for grant of concessional finance from Financial Institutions for starting industries. A techno-economic survey of these backward districts has also been undertaken by the State Directorate of Industries in collaboration with the Small Industries Service Institute and different Corporations of the State, namely, the U.P. Financial Corporation, the U.P. State Industrial Corporation and the U.P. Small Industries Corporation. A Joint Team sponsored by the Industrial Development Corporation of India, Industrial Finance Corporation, Industrial Credit and Investment Corporation of India, Reserve Bank of India and the Agricultural Refinance Corporation has completed a survey of U.P. with a view to identifying the industrial potentiality of the State. The survey report is under preparation. In addition, a survey of this district was made by the Small Industries Service Institute, Kanpur, in January 1970 wherein certain suggestions in regard to small industries have been made. The U.P. Government and Small Industries Organisation are engaged in locating prospective entrepreneurs for the setting up of industries in Bahraich. The actual setting up of industries in these districts would mainly depend on the initative of the entrepreneurs themselves and State agencies engaged in promotion of industries.

Enrolment of Bangla Desh refugees in the Voters List

2236. SHRI BIREN DUTTA : Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state :

(a) whether a number of displaced persons from Bangla Desh are being enlisted in the voters lists in Tripura; and

(b) if so, the steps Government propose to take to prevent this ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHARY) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

लघु उद्योग विकासायुक्त कार्यालय के तकनीकी अधिकारियों का विदेशों में भेजा जाना

2237. श्री जे. एन. मंडल : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योग विकासायुक्त कार्यालय के तकनीकी अधिकारियों को विदेश भेजने के क्या आधार हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशों को भेजे गये तकनीकी अधिकारियों के नाम तथा पद क्या हैं; उन्होंने किन देशों का दौरा किया और कितनी अवधि के लिए वे वहां ठहरे वहां उन्होंने किस प्रकार का कार्य किया तथा उन पर विदेशी मुद्रा का कितना व्यय हुआ; और

(ग) उन्हें विदेश भेजते समय उनकी वरिष्ठता को किस सीमा तक ध्यान में रखा गया ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) अधिकारियों का चुनाव मुख्यत: उनकी उपयुक्तता के आधार पर उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य, उनके अनुभव और अधिकारियों की क्षमता को ध्यान में रख कर किया जाता है ।

(ख) पिछले तीन वर्षों में विदेश भेजे गए अधिकारियों के नामों और पदों को दिखाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [ग्रन्थालय में रख दिया गया । देखिये संख्या LT--419/71] अधिकांश प्रतिनिधि मण्डल/डेप्यूटेशन विदेशी सरकारों के निमन्त्रण पर गये थे । अधिकारियों को दी गई अथवा उनके द्वारा खर्च की गई विदेशी मुद्रा की राशी की सूचना प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) अधिकारियों का चुनाव केवल वरीयता के आधार पर ही नहीं किया जाता है । फिर भी विदेश भेजे जाने वाले अधिकारियों का चुनाव करते समय अन्य चीजों के साथ अनुभव और वरीयता को भी ध्यान में रखा जाता है ।

पूंजीगत वस्तुओं के आयात हेतु लघु उद्योग के विकासायुक्त द्वारा स्वीकृत आवेदन पत्र

2238. **श्री जे. एन. मंण्डल** : क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : विकासायुक्त (लघु उद्योग) के कार्यालय के अधीन लघु उद्योगों विषयक समिति ने पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजीगत वस्तुओं के आयात हेतु कितने आवेदनपत्र स्वीकृत किये और पूंजीगत पदार्थों के ब्यौरे तथा उनके मूल्य सहित आवेदन पत्रों की राज्यवार संख्या क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : विगत तीन वर्षों में विकास आयुक्त, लघुउद्योग की लघु उद्योग समिति द्वारा स्वीकृत किए गये मामलों की संख्या नीचे दी गई हैं :—

वर्ष	स्वीकृत किये गये मामले	मूल्य (करोड़ रु० में)
1968-69	265	3.26
1969-70	305	3.64
1970-71	371	5.51
योग :—	940	12.41

राज्यवार मूल्य सहित स्वीकृत किए गये मामलों की संख्या के बारे में विस्तृत सूचना अभी उपलब्ध नहीं हैं । ऐसा अनुभव किया गया है कि इन 940 मामलों में मशीनों की विस्तृत जानकारी इकट्ठा करने में बहुत अधिक मेहनत और समय लगेगा ।